>

Title: Need to declare Bihar as an economically backward state and also to accord special status to the state.

श्री राम कृपाल यादव (पटना): मैं एकदम ब्रीफ में बोलूंगा।

माननीय सभापति महोदय, बिहार को आर्थिक पिछड़ा राज्य घोषित करने की मांग पिछले कई वर्षों से हो रही है, किन्तु केन्द्र सरकार इस पर अभी तक पूर्णरूपेण कोई कदम नहीं उठा रही है। बिहार की आर्थिक और आधारभूत संरचना की बदहाली सर्वविदित है। राज्य में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या 42 से 50 प्रतिशत है।[R73]

19.00 hrs.

बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति आय मात्र 1,610 रूपए सालाना है, जबकि राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय 20,858 रूपए है। वहां कुछ औद्योगिक इकाइयां भी थीं, जो मृतप्राय हैं। पिछले बीस-तीस वर्षों से बिहार में निवेश बंद पड़ा है। केंद्र सरकार ने एक भी कल-कारखाना खोलने के लिए गंभीर प्रयास नहीं किया। वैसे माननीय रेल मंत्री जी ने कुछ कल-कारखाने खोलने के लिए प्रयास किया, मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। बिहार में बाढ़ हर वर्ष तबाही के आलम लाती है और इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बिहार को अविलंब आर्थिक पिछड़ा राज्य घोषित करने और कम से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और नार्थ ईस्ट राज्यों की तर्ज पर विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार कदम उठाए।

मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि आप विशेष तौर पर इस पर निगाह रखें। बिहार की जो गरीबी और फटेहाली है, उसे दूर करने के लिए बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज देकर, बिहार के लोगों को मदद करने का काम करें।